साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 12, अंक : 2 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 7 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

मध्य प्रदेश-दूषित पेयजल में भोपाल भी पीछे नहीं, 6 साल में भोपाल-इंदौर में 5 लाख से अधिक लोग हुए बीमार

भोपाल मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई 15 मौतों के बाद भले ही यह मुद्दा गरम हो, पर आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश के दो सबसे बड़े शहर प्रदूषित पेयजल के कारण लंबे समय से बीमार हो रहे हैं। इंदौर और भोपाल दोनों को मिलाकर छह साल की अवधि में 5 लाख 45 हजार लोगों की जलजनित बीमारियों से पीड़ित होना पाया गया है। इसमें भी प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति ज्यादा खराब है। यहां पर छह साल के अंदर गंभीर पैचिस के चार लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की इन दोनों ही शहरों में जल प्रबंधन पर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 2013 से 2018 तक के आंकड़े सामने रखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिक निगम भोपाल के अंदर गंभीर पैचिस संबंधी मामले प्रतिवेदित किए गए हैं। 2013 से 2018 तक इनकी कुल संख्या 4,39,104 है, जबकि इसी अवधि में इंदौर में पैचिस के 40447 मामले दर्ज किए गए हैं। दूषित पानी का एक परिणाम टाइफाइड के रूप में सामने आता है। भोपाल में इस अवधि मं टाइफाइड के 39481 मामले सामने आए थे जबकि इंदौर में इसी अ वधि में 1462 मरीज प्रतिवेदित किए गए थे। वायरल हैपेटाइटिस के मामले भी भोपाल में 23875 थे जबकि इंदौर में 625 मामले दर्ज किए गए थे। बीमारियों के लिए समय पर पानी की जांच करना और रिपोर्ट

पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल और इंदौर में पानी की जांच के लिए नमूने तो लिए गए, इनका दूषित होना भी पाया गया, लेकिन इन पर कार्रवाई होने की कोई भी बात प्रशासन कैग को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवा पाया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 18 तक भोपाल में 299692 तक इंदौर में 74889 पानी के नमूने विभिन्न जल स्त्रोतों से एकत्र कर जांचे गए। भोपाल में 433 जैविक नमूने प्रतिकूल पाए गए, वहीं इंदौर में पानी का स्तर ज्यादा गंभीर पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में 3074 भौतिक, 147 रासायनिक तथा 827 में जीवाण्विक नमूने मानक स्तर 10500 से नीचे पाए गए। आपको बात दें कि पानी के नमूनों की जांच पानी के की जांच के लिए उसके भौतिक विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण, जीवाण्विक विश्लेषण और जैविक विश्लेषण किया जाता है। इंदौर में कम नमूने लिए जाने के बाद भी गुणवत्ताहीन पानी के नमूने ज्यादा पाए गए हैं, वहीं भोपाल में ज्यादा नमूनों के बाद भी स्थिति इंदौर से ज्यादा अच्छी बताई गई, वहीं भोपाल में बीमारियों के ज्यादा मामले पाए गए हैं। पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये लेखापरीक्षा द्वारा नगर पालिक निगमों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पानी के अगस्त एवं सितम्बर 2018 पानी के 54 नमूने लिए गए। भोपाल से 30 नमूने (स्त्रोत से 03, जलशोधन संयंत्र से 06, उच्च स्तरीय टंकियों से 06 तथा 15 नमूने उपभोक्ताओं से) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर से 24 नमूने (स्त्रोत से 02, जलशोधन संयंत्र से 04, उच्च स्तरीय टंकियों से 06 तथा 12 नमूने उपभोक्ताओं से) लिए गए। नमूनों की जांच स्वतंत्र रूप से राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला (एस.आर.एल.), भोपाल से कराई गई। भोपाल के दो नमूनों में गंदलापन बी.आई. एस. 10500 मानदंडों के प्रतिकूल, तीन में फिक्ल कॉलीफार्म मानक शून्य के विरूद्ध 30 से 60 की संख्या में था। इन्दौर के पांच जल नमूनों में मानदंड के अनुसार नहीं था। पर इस दल की जांच को यह नगर पालिक निगम ने खारिज ही कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नमूने लिए जाने की प्रक्रिया तथा जांच दोषपूर्ण है।

इंदौर में 1215 करोड़ और भोपाल में 156 करोड़ खर्च नहीं हो पाए ऐसा नहीं है कि बेहतर व्यवस्था के लिए नगर निगम के पास बजट नहीं था। पांच साल का विश्लेषण बताता है कि दोनों ही शहरों में में इन व्यवस्थाओं के लिए जितना बजट प्राप्त हुआ, उतना व्यय नहीं हो पाया है, हर साल बजट बचा ही रह गया। पांच साल में भोपाल नगर निगम को लगभग 1119 करोड़ का बजट आवंटन हुआ, जिसमें से 963 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। 156 करोड़ रुपए बचे रह गए। संचालनालय एंव नगर पालिक निगम बजट के अनुसार इसी अवधि में इंदौर नगर निगम को 2352 करोड़ रुपए की प्राप्ति बताई गई जिसमें से 1137 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। 1215 करोड़ रुपए बचे रह गए। -सोर्स डाउन टू अर्थ

45 वेटलैंड पर 50 से अधिक प्रजातियों के 5 हजार पक्षी दर्ज

देवास (संवाददाता द्वारा) जिले में एशियाई जलपक्षी गणना (एशियन वाटर बड्स सेंसस)-2026 का आयोजन किया गया। वन विभाग के मार्गदर्शन में हुई इस गणना का मुख्य उद्देश्य देवास के वेटलैंड्स की स्थिति का आकलन करना और जलीय पक्षियों की प्रजातियों व संख्या का पता लगाना था। यह पहल सिटिजन साइंस के तहत बर्ड वॉचर्स और आम जनता की भागीदारी के साथ की गई।

वन विभाग देवास के एशियाई जलपक्षी जनगणना 2026 के नोडल अधिकारी विकास माहोरे के निर्देशन में यह गणना संपन्न हुई। इसके लिए देवास के छोटे-बड़े तालाबों, नदियों, डेम और बांधों के आसपास स्थित 45 वेटलैंड स्थलों का चयन किया गया था। गणना के दौरान देवास शहर के मीठा तालाब पर नॉब बिल्ड डक जैसी एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई। पूरे देवास जिले के 45 वेटलैंड स्थलों पर 50 से अधिक प्रजातियों के लगभग 5000 पक्षियों को दर्ज किया गया। यह पहली बार था जब मध्य प्रदेश ने एशियाई जलपक्षी जनगणना 2026 में भागीदारी की। राज्य ने गणना के लिए सर्वाधिक स्थल चयन कर और सर्वाधिक चेकलिस्ट जमा करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर वेटलैंड्स और जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। यह जानकारी डिप्टी रेंजर हेमराज गोखले द्वारा दी गई।

श्रीकाकुलम में बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट में पर्यावरण मानकों की अनदेखी, एनजीटी की समिति ने उठाए सवाल

श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित एक कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। श्रीकाकुलम जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 23 दिसंबर 2025 को इस बारे में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है।

इस रिपोर्ट में बताया कि रेनबो इंडस्ट्रीज, जो पाथा कुंकम गांव (लावेरु मंडल) में स्थित है, पर्यावरण मानकों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर गठित संयुक्त समिति ने 2 जुलाई 2025 को इस संयंत्र का निरीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट 21 अगस्त 2025 को सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार यह संयंत्र श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरमन्यम और विजयनगरम जिलों में फैली स्वास्थ्य सुविधाओं से हर दिन करीब 792.89 किलोग्राम बायो-मेडिकल कचरा एकत्र कर उसका निपटान करता है। यह कचरा कुल 13,274 बिस्तरों वाले अस्पतालों और गैर-बिस्तरयुक्त स्वास्थ्य केंद्रों से आता है। यह कार्य संयंत्र की स्वीकृत क्षमता के भीतर किया जा रहा है। हालांकि, समिति ने कई गंभीर खामियों की ओर भी इशारा किया है। संयंत्र में बिना प्रोसेस हुए बायो-मेडिकल कचरे को स्टोर करने की व्यवस्था तो है, लेकिन रंग-कोड के अनुसार कचरे को अलग-अलग रखने के लिए अलग कमरा नहीं है। सभी प्रकार का कचरा एक ही स्थान पर अलग-अलग करके रखा जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है।

इंसीनरेटर की चिमनी से निकले उत्सर्जन की जांच में यह सामने आया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और पारे का स्तर तय मानकों के भीतर है। लेकिन पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जहां मानक 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर है, वहीं इसकी मात्रा 65 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, इंसीनरेटर की दहन क्षमता भी मानक से कम पाई गई। जहां नियमों के अनुसार 99 फीसदी दहन क्षमता आवश्यक है, वहीं यह महज 98.5 फीसदी रही।

संयंत्र से रोजाना औसतन 19.04 किलोग्राम राख निकलती है। इसके साथ फ्ल्यू गैस ट्रीटमेंट से निकला अवशेष और ईटीपी स्लज को आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम लिमिटेड के माध्यम से कोस्टल वेस्ट मैनेजमेंट की पारवाड़ा स्थित टीएसडीएफ सुविधा में भेजा जाता है। इंसीनरेटर की राख के विश्लेषण में भी गंभीर गड़बड़ी सामने आई। लॉस ऑन इग्निशन तय पांच फीसदी की सीमा के मुकाबले 19.97 फीसदी पाया गया, जबकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी मानक (तीन फीसदी) से अधिक, यानी 3.72 फीसदी दर्ज की गई।

संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि संयंत्र पार्टिकुलेट मैटर, डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे खतरनाक प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करे और इंसीनरेटर की दहन क्षमता को निर्धारित मानकों तक पहुंचाए। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2014 से 2024 के बीच पाई गई अनियमितताओं को लेकर सीबीडब्ल्यूटीएफ के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन ताजा रिपोर्ट से साफ है कि सुधार अब भी अधूरे हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली मंडल के मार्तुरु, माकवरम और रेबका गांवों में चल रही सभी खनन इकाइयां और स्टोन क्रशर वैध अनुमति के साथ संचालित हो रहे हैं। यह जानकारी 20 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) द्वारा दायर रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन गांवों में कुल 19 खनन इकाइयां और 17 स्टोन क्रशर सक्रिय हैं। सभी इकाइयों के पास 'कंसेंट टू ऑपरेट' (सीटीओ) यानी संचालन की वैध अनुमति मौजूद है। हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन इकाइयों पर सख्त निगरानी रखे हुए है। जांच के दौरान कुछ स्टोन क्रशरों के आसपास निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम) का स्तर तय मानकों से अधिक पाया गया। इस पर संबंधित इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं और नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 31 जनवरी से 1 फरवरी 2025 के बीच मार्तुरु गांव में वायु गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान पीएम10 का स्तर निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया। इसके बावजूद, एपीपीसीबी ने स्पष्ट किया है कि स्टोन क्रशर और खनन इकाइयों पर नियमों के सख्त पालन के लिए लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी इकाई के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खनन और ब्लास्टिंग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी खनन एवं भूविज्ञान विभाग की है, जबकि फसल नुकसान और मुआवजा एपीपीसीबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

महाकौशल को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान?

उद्योग-पर्यावरण क्षेत्र ने सराहा सरकार का काम

जबलपुर। महाकौशल क्षेत्र में विकास कार्य, रोजगार सृजन तथा पर्यावरण महत्व के संबंध में हुए कार्यों पर औद्योगिक और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित बुद्धिजीवी वर्ग ने कार्य की सराहना की है। उनका कहना है कि दो वर्षों में कई विकास कार्य हुए हैं। अपार संभावना है कि महाकौशल क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान मिल सकता है।

जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे का कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए जबलपुर में इंनवेस्टर समिट करवाया गया था। इसके अलावा प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात जबलपुर को मिली। नर्मदा घाट को अयोध्या जैसा विकसित किया जा रहा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। महाकौशल क्षेत्र में तीन टाइगर रिजर्व आते हैं। वन्य प्राणियों को देखने के लिए विदेश से सैलानी आते हैं। सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाये तो महाकौशल क्षेत्र विश्व मानचित्र में पर्यटन हक के रूप में उभर सकता है। इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र में मटर का उत्पादन बहुत होता है और गुड़ भी बनता है। इसके अलावा वन संपदा भी बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में भी सरकार को कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। व्यापार क्षेत्र से जुड़े राजीव बडेरिया का कहना है कि दो साल के कार्यकाल से स्पष्ट है कि विकास कार्यों के संबंध में प्रदेश सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है। महाकौशल तथा बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार के कई सौगात दी है। भेड़ाघाट भी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है और उसका विकास और विकास के साथ प्रचार-प्रसार भी आवश्यक है, जिससे उसे उसका वास्तविक हक मिल सके। यातायात सुविधा से क्षेत्र का विकास होता है। सड़क के निर्माण पर प्रदेश सरकार विशेष ध्यान दे रही है। महाकौशल क्षेत्र को पर्यटन की आभार संभावना है। जबलपुर में कई फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिससे शहर का यातायात सुगम होगा।

साल बोरर की वापसी–15 साल के पेड़ों के दुश्मन कीट ने बजाई खतरे की घंटी

डिंडोरी (एजेंसी)मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सोनतीरथ गांव के जंगल की खामोशी अचानक पेड़ों पर चलने वाली कुल्हाड़ी की आवाज से भंग होती है। इस घने जंगल में चारों ओर से आती इन आवाजों को सुनकर एक बार तो लगा कि शायद पेड़ों की अवैध कटाई करने वाला कोई गिरोह सक्रिय है। जंगल में कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर सुस्ता रहे 70 साल के मजदूर सुकाल ने हमारी यह गलतफहमी मिनटों में दूर कर दी। उन्होंने जानकारी दी कि वह पेड़ काट नहीं रहे हैं बल्कि उनकी पहचान कर रहे हैं। सुकाल कुल्हाड़ी की मदद से साल के पेड़ के तने को छीलकर आयताकार शक्ल दे रहे हैं। इस काम में उन्हें जरा भी खुशी नहीं मिल रही है। माथे पर शिकन लिए सुकाल ने केवल इतना ही कहा, पूरा जंगल रो रहा है। यह बहुत तेजी से सूख रहा है।

सुकाल का इशारा साल (शोरिया रोबस्टा) के पेड़ों पर लगने वाले तना छेदक कीट (साल बोरर अथवा होप्लोसिराम्बिक्स स्पाईनिकॉर्निस) की तरफ था। यह साल के जंगल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। लगभग 30 साल पहले (1996–2001) इसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में जमकर तबाही मचाई थी। सुकाल के साथ करीब 35 मजदूर थे जो साल के उन पेड़ों को चिन्हित कर रहे थे जिन पर साल बोरर का प्रभाव था। इन्हीं में से एक 45 वर्षीय मजदूर सोहनलाल बैगा ने पेड़ के चारों तरफ फैले क्रीमी बुरादे की ओर उंगली से इशारा करते हुए बताया, ये सभी पेड़ साल बोरर से सूख रहे हैं। सोनतीरथ गांव के इस घने जंगल में 30 नवंबर 2025 से पेड़ों की पहचान और उनकी मार्किंग का काम शुरू हुआ है। एक मजदूर रोजाना साल बोरर प्रभावित करीब 100 पेड़ों की छाल निकालकर उन्हें मार्किंग के लिए तैयार कर रहा है। इस काम में लगे मजदूर एकसुर में स्वीकार करते हैं कि इस वर्ष साल बोरर ने जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके अनुसार, पिछले 4–5 वर्षों से साल बोरर का हल्का असर था, लेकिन इस वर्ष हालात ज्यादा ही खराब हैं। उन्होंने माना कि मार्किंग किए गए पेड़ों को काटा जा सकता है क्योंकि साल बोरर पेड़ों का रस चूसकर सुखा देता है और इन पेड़ों को काटना ही पड़ता है। वन विभाग ने गांव के इस 119.25 हेक्टेयर जंगल को एससीआई (सिलेक्शन कम इंप्रूवमेंट) कूप संख्या 776 में सूचीबद्ध किया है। 3 दिसंबर 2025 तक केवल 3 हेक्टेयर में ही मार्किंग का काम हुआ था और तब तक साल बोरर प्रभावित 3,113 पेड़ों को गिना गया था। मजदूरों ने बताया कि पूरे 119.25 हेक्टेयर जंगल की मार्किंग में एक महीना तक लग सकता है और केवल इसी गांव के जंगल में प्रभावित पेड़ों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि 14 नवंबर को मार्किंग के काम में लगे एक मजदूर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बाद में पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने साल बोरर प्रभावित बहुत से पेड़ों को गणना से बाहर कर दिया है। इसके बावजूद सोनतीरथ के 119.25 हेक्टेयर के जंगल में साल बोरर प्रभावित पेड़ों की संख्या करीब 5,000 पहुंच गई।

साल के पेड़ पारिस्थितिकी और आर्थिक दृष्टि से सागौन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। जबलपुर स्थित उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई) के एक दस्तावेज के अनुसार, भारत में साल वन लगभग 1,05,790 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 28,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से में है। यह पूरे देश में साल वन क्षेत्र का 25 प्रतिशत है। वनों में पाए जाने वाले अन्य वृक्षों की तुलना में साल में सबसे अधिक कीट पाए जाते हैं। इनमें लगने वाली करीब 339 कीट प्रजातियों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साल वनों में वृक्ष की सभी अवस्थाओं में साल बोरर का सर्वाधिक प्रकोप पाया जाता है जो वृक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह कीट साल के तने को भेदकर उसे खाता और अंदर सुरंग बनाकर रहता है। टीएफआरआई के एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस कीट ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्हें मध्य प्रदेश के डिंडोरी और अमरकंटक के अलावा छत्तीसगढ़ के चिल्पी, गरियाबंद और नारायणपुर क्षेत्र में इसके फैलने की सूचनाएं मिल रही हैं। डिंडोरी के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) पुनीत सोनकर डाउन टू अर्थ से बातचीत में स्वीकार करते हैं कि पिछले दो वर्षों से साल बोरर प्रभावित पेड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष भी साल बोरर प्रभावित लगभग 5,000 से 6,000 पेड़ों को चिन्हित किया गया था। उनका कहना है, इस वर्ष अभी चिन्हांकन की प्रक्रिया जारी है। जब आंकड़े आ जाएंगे, तब हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोनकर के अनुसार, स्थानीय स्टाफ और ग्रामीण पूर्व करंजिया रेंज, पश्चिम करंजिया रेंज और दक्षिण समनापुर क्षेत्र में इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। हालांकि जब तक आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक इसे गंभीर या चिंताजनक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हां, साल के पेड़ मध्यम स्तर पर प्रभावित हैं। पेड़ों के नीचे लगातार बुरादा मिल रहा है।वह आगे कहते हैं, पूर्व और पश्चिम करंजिया, दक्षिण समनापुर, उत्तरी समनापुर, बजाग, अमरपुर, डिंडोरी और शाहपुर रेंज में साल के जंगल अधिक हैं। इसलिए सभी जगह गणना की जा रही है।साल बोरर का पहला संकेत गांवों से मिलता है। ये कीट घरों की रोशनी के पास जमा होने लगते हैं।

मुख्यमंत्री इन्दौर के भागीरथपुरा के प्रभावितों और परिजनों से मिल

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन्दौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से पीड़ित और प्रभावितों से मिलकर भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता न करें, सब कुछ अब ठीक होगा। आप सभी पूर्णत: स्वस्थ होकर अपने घर सकुशल पहुँचेंगे। यहाँ आपको बेहतर से बेहतर उपचार निःशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि सभी प्रभावितों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाये साथ ही इसकी निगरानी भी हो। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावितों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावितों और उनके परिजनों से कहा कि राज्य शासन आपके साथ है। उन्होंने प्रभावितों तथा परिजनों के जीवन निर्वाह, कामकाज आदि के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा विशेषज्ञ और अस्पताल स्टॉफ से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने अधिकरियों और चिकित्सकों को निर्देश दिये कि वे अस्पताल में भर्ती प्रभावितों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखें। प्रभावितों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ, निःशुल्क दवायें, इंजेक्शन, जाँच और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाये। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने अधिकारियों को कहा कि यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में भागीरथपुरा में हुई घटना के प्रभावितों से मिलने 31 दिसम्बर की शाम को परदेशीपुरा स्थित वर्मा अस्पताल, नंदानगर स्थित बीमा अस्पताल,एमआईजी चौराहा स्थित डीएनएस अस्पताल, रेसकोर्स रोड़ स्थित शैल्बी अस्पताल, एम.वाय.अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में पहुँचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावितों से अस्पताल में उपलब्ध कराए जा रहे उपचार तथा अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व निर्मित हुई स्थितियों

ताप्ती जल से हर घर तक शुद्ध जल

बुरहानपुर जल आवर्धन योजना से बदल रही तस्वीर

तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण

भोपाल ताप्ती नदी आधारित ''जल आवर्धन योजना'' से बुरहानपुर शहर को एक आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद जल आपूर्ति प्रणाली मिली है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नगरपालिक निगम बुरहानपुर द्वारा किया गया है। बुरहानपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के बीच सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

बुरहानपुर शहर की जल वितरण अधोसंरचना पुरानी हो गई थी, जिससे जलापूर्ति ट्यूबवेलों लीकेज, गंदगी की मिलावट का खतरा था। गिरता भूजल स्तर जल की भविष्य की सुचारू उपलब्धता संकट था। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए ताप्ती नदी आधारित नई जलप्रदाय प्रणाली विकसित की गई है। इसके तहत एनीकट, इंटेकवेल और 50 एमएलडी क्षमता का अत्याधुनिक जलशोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। जल शोधन संयंत्र में पानी को फिल्ट्रेशन क्लोरीनेशन और अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से शुद्ध किया जाता है। स्काडा प्रणाली से गुणवत्ता और आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जाती है। पानी की क्वालिटी की रोज़ाना मॉनिटरिंग के लिए डब्ल्यूटीपी में एक हाई-लेवल वॉटर टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। शुद्ध जल को 8 नए ओवरहेड टैंक और बेहतर पाइप नेटवर्क से शहर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पुराने और क्षतिग्रस्त पाइपों को हटाकर नया वितरण नेटवर्क बिछाया गया है। बुरहानपुर में लगभग 41 हजार घरों में मीटरयुक्त नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, इससे लीकेज पर नियंत्रण हुआ है, जल के अपव्यय में कमी आई है और जल वितरण व्यवस्था अधिक सुचारु हुई है। वर्तमान में नगरवासियों को प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन मिल रहा है। बुरहानपुर में 275 ट्यूबवेल से जलापूर्ति

की जा रही थी, नई प्रणाली से टैंकरों और ट्यूबवेल पर निर्भरता लगभग समाप्त हुई है। क्षेत्र में निरंतर गिरते भूजल स्तर के की समस्या का भी निराकरण होगा। योजना के क्रियान्वयन से लगभग 8 करोड़ की बचत होगी। अब तक नगर निगम द्वारा भूजल आधारित योजना के संचालन संधारण पर वार्षिक व्यय लगभग रूपये 10 से 12 करोड़ था। अब यह व्यय लगभग रूपये 4 करोड़ होगा। प्रत्येक घर में पंजीकृत नल कनेक्शन सुरक्षित जल उपयोग, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामुदायिक जिम्मेदारी के प्रति स्थायी व्यवहार परिवर्तन की सोच के साथ, एमपीयूडीसी द्वारा व्यापक स्तर पर संपर्क किया गया। नवीन जल तंत्र में विश्वास को जगाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए घर-घर सर्वेक्षण, सामुदायिक परामर्श और फोकस समूह बैठकें और व्यापक सामाजिक आंकलन किया गया। परियोजना के पूर्ण होने के बाद जलजनित रोगों में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुरहानपुर जल आवर्धन योजना ने शहर को सुरक्षित, स्वच्छ और सतत् जल आपूर्ति की मजबूत नींव दी है। यह पहल स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण को मजबूती भी दे रही है।

सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्यग्रहण 2027 में, पूरी दुनिया में छा जाएगा अंधेरा

वॉशिंगटन । वैज्ञानिकों के लिए सूर्यग्रहण दिलचस्पी का केंद्र रहा है। 2 अगस्त 2027 को धरती पर सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्यग्रहण पड़ेगा। इस दौरान 6 मिनट 23 सेकंड तक ग्रहण के चलते आसमान में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि क्या पूर्ण सूर्यग्रहण पर पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। इसके लिए हमें ग्रहण को समझना होगा कि वे कैसे काम करते है और उनकी अंधेरा करने की क्षमता किसी क्षेत्र विशेष पर कैसे असर डालती है। बता दें सूर्यग्रहण एक खगोलीय घटना है, जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के क्रमश: एक सीध में आने के चलते होती है। पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब चांद सीधी रेखा में सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इस संयोजन के चलते सूर्य का कोरोना चांद के पीछे छिप जाता है और पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है। इससे आसमान में शाम जैसा नजारा नजर आता है। इस परछाई को अंब्रा कहते हैं। अंब्रा काफी पतली होती है। अंब्रा कुछ दर्जन से लेकर कुछ सौ किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो सकती है जो एक घुमावदार लाइन बनाती है। इसे पाथ ऑफ टोटैलिटी यानी ग्रहण का मार्ग कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस पतले मार्ग पर आने वाले लोगों को ही ग्रहण का अंधेरा महसूस होता है। यही वजह है कि कोई भी सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया में एक साथ नहीं कर सकता। इसमें 2027 का पूर्ण सूर्यग्रहण भी शामिल है। पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर या थोड़ी छाया पड़ती है या बिल्कुल नहीं पड़ता। यह निर्भर करता है कि वे कितनी दूर हैं। पृथ्वी बड़ी है और लगातार घूमती रहती है। इसलिए चांद की छाया एक हिस्से पर ज्यादा देर नहीं पड़ती है। 2027 का पूर्ण सूर्यग्रहण अपनी लंबाई के चलते बेहद खास हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि उस दौरान सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होगा जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसके चलते यह बड़ा दिखेगा और ज्यादा समय तक छाया को रोकेगा। इस अवधि का पूर्ण सर्यग्रहण 2114 तक नहीं देखा जा सकेगा। यही वजह है कि इसे सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2027 को होने वाला पूर्ण सूर्यग्रहण पूर्वी अटलांटिक से शुरू होगा। यह उत्तरी अफ्रीका से होते हुए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। मिस्र के लक्सर और असवान में सबसे लंबे समय तक ग्रहण रहेगा। पूर्ण सूर्यग्रहण में आसमान में अंधेरा छा जाएगा। तापमान कम हो सकता है और सूर्य का कोरोना डिस्क के चारों ओर हल्ला चमकेगा। ज्यादातर यूरोप, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्से और पूर्वी अफ्रीका के हिस्से आंशिक दृश्यता वाले क्षेत्र में आएंगे। भारत समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में इस ग्रहण का कोई असर नहीं होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008